बढ़ने लगा जल संकट, नल जल योजनाओं की पूर्णता पर सवाल

हैंडपंपों के संधारण की स्थितियां खराब, पीएचई विभाग का निगरानी तंत्र फेल, पेयजल के लिए करोड़ों स्वाहा होने के बाद भी पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं

नवभारत न्यूज

पन्ना 26 अप्रैल। पेयजल एवं जलसंरक्षण के नाम पर तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं नेता एवं जनप्रतिनिधि फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं फिर विभागीय अमला बजट ठिकाने का खेल खेलता है और अभियान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है यही कारण है कि जलसंरक्षण एवं पेयजल के लिए जितने अभियान चले सब विफल रहे क्योंकि विभागीय अमले की खाउकमाउ नीति के चलते बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहा और समस्या यथावत बनी रही ।

अफसरों के फोन बंद, जल स्तर पहुंच रहा नीचे, हैंडपंपों की स्थिति खराब, नल जल योजनाओं में कहीं बिजली का संकट तो कहीं कनेक्शन एवं पानी का अभाव, पीएचई विभाग पोर्टल में बता रहा प्रगति किन्तु जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ज्ञात हो प्रतिवर्ष जिले में पानी का संकट पैदा होता है किन्तु मानक के अनुसार एवं मांग के अनुसार पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। जिन गांवों में पानी की समस्या गंभीर होती है वहां लोगों को पानी के लिये भटकना पड़ता है। पीएचई के पोर्टल के माध्यम से आंकड़ों के माध्यम से पानी मिल सकता है। जल निगम भी आंकड़ों के माध्यम से पानी दे सकता है। किन्तु वास्तविक रूप से नागरिकों को कितना पानी मिल पाता है यह तो वही बता सकता है। अथवा जब उसकी आवाज उठेगी तब बात सामने आयेगी। वर्तमान समय पर जल गंगा संवर्धन अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान की समीक्षा भी की जा रही है। कई विभागों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित की गई है। पीएचई विभाग की भी जिम्मेदारियां होंगी किन्तु अफसरों व अमले को लगता है कि ये आपदा में अवसर है इसलिये योजनाओं के कागजी क्रियान्वयन के नाम पर जितना हो सके उतना लूटो और फर्जी उपलब्धियों एवं आंकड़ों के आधार पर पानी की उपलब्धता की पूर्ति दिखाते रहो।

कई योजनाओं का बजट पानी में ही खर्च होता है

यह भी सही है कि प्रतिवर्ष पानी के नाम पर सरकारी योजनाओं को बहुत सारा बजट खर्च होता है। पीएचई विभाग जहां जल जीवन मिशन के माध्यम से अरबों का बजट स्वाहा कर रहा है। वहीं हैंडपंपों के नाम पर भी कई करोड़ की निविदायें प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त जनजातीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम पंचायतों की योजनाओं से नये-नये हैंडपंपों का खनन किया जाता है। विधायक मद, सांसद मद से लेकर डीएमएफआदि मदों का बजट भी पानी की योजनाओं में खर्च किया जाता है। इस तरह से समझा जा सकता है कि प्रतिवर्ष कई करोड़ का बजट पानी में खर्च हो रहा है। फिर भी जनता को संकट के समय उसकी मांग के अनुसार पानी नहीं मिलता। अभी तक स्पष्ट रूप से यह भी पता नहीं है कि पीएचई, पंचायत, ट्राईबल, विधायक एवं सांसद मदों से कितने हैंडपंप खनित किये जा चुके हैं। आंकड़ों को देखा जाय तो हर गांव में पर्याप्त संख्या में हैंडपंप स्थापित हैं किन्तु संकट के समय पर कितने हैंडपंप चल रहे हैं कितने बंद हैं, कितने खराब हो चुके हैं इसका भी सही-सही हिसाब नहीं मिल सकता।

हर घर नल से जल के नाम जल जीवन का हाल

केन्द्र सरकार ने जल जीवन मिशन के नाम पर हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना लागू किया गया। एकल योजनाओं के नाम पर कई गांवों में करोड़ों की राशि खर्च हुई। कहीं टंकियों का निर्माण, पाईप लाईनों के माध्यम से पानी देने की योजना बनी। कई योजनायें कागजों में ही पूरी हो गईं। कई योजनाओं का सही तरीके से ट्रायल रन भी नहीं हो पाया। कई करोड़ो स्वाहा होने के बाद भी अभी तक लक्षित गांवों तक योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन शुरू नहीं हो पाया। हाल ऐसा है कि ट्रायल के लिये पानी की नवीन टंकियों को जब भरा जाता है तो वे पानी का लोड बर्दाश्त नहीं कर पातीं। लिहाजा भरभराकर ढह जाती हैं। यह गुणवत्ता की स्थिति है जो बताती है कि मिशन की योजनाओं में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के सामने ठेकेदारों ने पानी की टोटी स्थापित कर दी किन्तु पाईप लाईन ही नहीं डाली। कई जगह अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया। कई गांवों में बोर कर दिये गये किन्तु कनेक्शन ही नहीं हुये। इसी तरह से जल निगम की स्थितियां हैं। जिले की पहली समूह नल जल योजना अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई। लिहाजा लक्षित सभी गांवों तक पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया। निर्माण की समय सीमा वर्षों पूर्व ही समाप्त हो चुकी है।

6 परीक्षा केन्द्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा

नवभारत न्यूज

पन्ना 26 अप्रैल। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 जिला मुख्यालय पन्ना के 6 परीक्षा केन्द्रों पर रविवार को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। आयोग के निर्देश मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा सभी केन्द्रों पर परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे।

उड़नदस्ता दल के गठन सहित परीक्षा संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यक दायित्व भी सौंपे गए थे। पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दो सत्रों में संपन्न हुई। समस्त केन्द्रों पर कुल 1765 परीक्षार्थियों को शामिल होना था।

सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 1406 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 359 अनुपस्थित रहे। इसी तरह द्वितीय सत्र में दोपहर 2:15 बजे से अपरान्ह 4:15 बजे तक सामान्य अभिरूचि परीक्षण के प्रश्न पत्र में 1396 परीक्षार्थी शामिल हुए एवं 369 अनुपस्थित रहे।

विधायक कार्यालय अमानगंज में स्वास्थ्य परामर्श शिविर हुआ

नवभारत न्यूज

अमानगंज 26 अप्रैल। गत दिवस विधायक कार्यालय परिसर अमानगंज में एक दिवसीय स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन विधायक गुनौर राजेश कुमार वर्मा के सहयोग से शैलबी हॉस्पिटल, जबलपुर के कुशल चिकित्सकों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

शिविर में जबलपुर से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श प्रदान किया। इस दौरान डॉ. प्रशांत जैन (ऑन्को सर्जन), डॉ. अतुल दुबे (कार्डियोलॉजिस्ट), डॉ. दीपांशु साहू (जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन), डॉ. स्वीटी श्रीवास्तव तथा डॉ. विश्वनाथ प्रताप सिंह (जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन) ने मरीजों का उपचार किया। शिविर में कुल 75 मरीज उपचार के लिए पहुंचे, जिनमें से कैंसर एवं सर्जरी से संबंधित मरीजों को चिन्हित किया गया। चिन्हित मरीजों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया गया। कार्यक्रम के आरंभ में पूजन एवं दीप प्रज्ज्वलन उपरांत आयोजक विधायक श्री वर्मा द्वारा सभी चिकित्सकों का पौधा भेंटकर सम्मान किया गया। उपस्थित चिकित्सकों ने भी कार्यक्रम की सराहना की और विधायक के प्रयासों से जरूरतमंद व्यक्तियों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा मिलने पर प्रसन्नता जताई। इस अवसर पर विधायक राजेश वर्मा ने कहा कि पन्ना एक छोटा जिला है। यहां चिकित्सक और चिकित्सा सेवाएं कम हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई बार मिलने वाले गंभीर बीमारी के मरीजों सहित अन्य लोगों के समुचित उपचार के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है।

जिला जेल पन्ना एवं सब जेल पवई में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण एवं विधिक सहायता शिविर आयोजित

नवभारत न्यूज

पन्ना 26 अप्रैल। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर के निर्देशानुसार व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शरत चन्द्र सक्सेना के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला जेल पन्ना में महिला व पुरुष बंदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण एवं विधिक सहायता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में सचिव श्री गौड़ द्वारा जेल बंदियों को उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन बंदियों के जमानत लाभ देने संबंधी आदेश सहित जमानत आदेश उपरांत जमानत प्रस्तुति में आ रही समस्याओं का निराकरण के बारे में अवगत कराया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन द्वारा बंदियों से संवाद कर प्ली ऑफ बारगेनिंग के प्रावधान व प्रक्रिया, बंदियों के अधिकार निःशुल्क विधिक सहायता, बंदियों के जमानत यूटीआरसी के क्रियान्वयन, पैरोल, समय पूर्व बंदियों की रिहाई आदि कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से

बताया गया। प्रभारी जेल अधीक्षक जी.के. सिंह ने आभार प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला जेल व स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु गठित चिकित्सकों की टीम द्वारा महिला व पुरुष बंदियों का चिकित्सीय परीक्षण कर आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवाईयों का वितरण किया गया। इसी तरह सब जेल पवई में अपर सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति पवई सोम पाण्डेय की उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर एवं स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया।

अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा बंदियों को विधिक सहायता संबंधी जानकारी प्रदान की गई। बंदियों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर स्वास्थ्य कैंप में अपनी बीमारी के संबंध में चिकित्सक से चर्चा कर परामर्श प्राप्त करने की सलाह भी दी गई।

बंदियों को दी गई विधिक सहायता संबंधी जानकारी

विधिक सहायता संबंधी जानकारी अधिवक्ता राधिका प्रसाद पटेल एवं के.पी. तिवारी द्वारा बंदियों को प्रदाय की गई। जेल में आयोजित स्वास्थ्य कैंप में परिरुद्ध सभी 97 बंदियों का बीपी, शुगर, पल्स एवं सामान्य बीमारी से पीड़ित बंदियों का परीक्षण कर उपचार दिया गया। कोई भी बंदी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं पाया गया। कैंप के समापन पर सहायक जेल अधीक्षक मुनीन्द्र प्रसाद मिश्रा द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

संघ की जन गोष्ठी में पंच परिवर्तन का संदेश

शताब्दी वर्ष पर समाज जागरण का आह्वान

नवभारत न्यूज

पन्ना 26 अप्रैल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज पन्ना नगर के टाउन हॉल में प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, समाजसेवियों और स्वयंसेवकों की उपस्थिति रही।

मंच पर उपस्थित जिला संघचालक रुद्रप्रताप यादव एवं मुख्य वक्ता क्षेत्र सह कार्यवाह हेमन्त मुक्तिबोध ने संघ की 100 वर्षों की यात्रा और उसके सामाजिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने बताया कि संघ की स्थापना वर्ष 1925 में नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी और तब से लेकर आज तक संघ ने अनेक चुनौतियों और आरोपों के बावजूद निरंतर समाज सेवा का कार्य किया है।

मुख्य वक्ता हेमन्त मुक्तिबोध ने अपने उद्बोधन में पंच परिवर्तन की अवधारणा को विस्तार से समझाया। उन्होंने कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी तथा नागरिक कर्तव्य जैसे विषयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन मूल्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

उन्होंने भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने और समाज को संगठित करने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदारी के साथ पंच परिवर्तन को अपने जीवन में उतार ले, तो भारत निश्चित ही एक शक्तिशाली, सशक्त और पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर होगा।

नगायच बने म.प्र. वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, मंत्री का दर्जा मिलने से समर्थकों में खुशी

नवभारत न्यूज

पन्ना 26 अप्रैल। गत दिवस म0 प्र0 शासन ने निगम एवं मण्डलों में नियुक्तियां की है जिसमें पन्ना जिले

भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर युवा नेता और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पन्ना के पूर्व अध्यक्ष संजय नगायच को मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (म.प्र. वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन) का अध्यक्ष नियुक्त कर मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस नियुक्ति की खबर मिलते ही उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया।संजय नगायच की गिनती बुंदेलखंड के तेज-तर्रार और प्रभावशाली युवा नेताओं में होती है। वे बाल्यकाल से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं इसके पूर्व कोआपरेटिव बैंक पन्ना के चेयरमैन भी रह चुके हैं ।

कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

नवभारत न्यूज

पन्ना 26 अप्रैल। कलेक्टर ऊषा परमार की अध्यक्षता में गत शुक्रवार को कलेक्टर कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस मौके पर जिले में व्यवस्थित एवं सुचारू यातायात व्यवस्था एवं प्रबंधन सहित सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के दृष्टिगत आवश्यक उपायों पर चर्चा कर वांछित कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा विभिन्न चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के मद्देनजर रोड एजेंसी को गति सीमा बोर्ड, रम्बल ट्रीप, ब्रेकर, सांकेतिक बोर्ड, रोड मार्किंग इत्यादि के कार्य प्राथमिकता से समय सीमा में सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर जिला अस्पताल के निकट लापरवाह दुकानदारों के विरूद्ध सतत् कार्यवाही एवं सामग्री जप्ती सहित जुगल किशोर मंदिर प्रांगण एवं परिसर पहुंच मार्ग की सुचारू यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत भी जरूरी निर्देश दिए।

कलेक्टर श्रीमती परमार ने नेशनल हाईवे 39 पन्ना-छतरपुर मार्ग पर डायमंड चौराहा से मनौर ढाबा तक की क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत सहित विभिन्न स्थानों पर गति सीमा नियंत्रण के लिए मापदण्ड अनुसार स्पीड ब्रेकर बनवाने, भैरव घाटी में रोड कॉर्नर पर फिलिंग कार्य, सतत् पेट्रोलिंग तथा पन्ना नगर में रविवारीय बाजार के दिवस निर्धारित क्षेत्र में चार पहिया वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध एवं पार्किंग स्थल चिन्हांकित कराने, क्रेन की व्यवस्था व सड़कों से निराश्रित गौवंश को उपयुक्त स्थल पर विस्थापित करने के लिए भी कहा। साथ ही मड़ला घाटी क्षेत्र के लगभग तीन किमी के नेटवर्कविहीन सड़क क्षेत्र में कैमरा एवं सोलर लाइट की व्यवस्था के दृष्टिगत प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

शहर के चारों कोने पर बनेगे रिक्शा स्टैण्ड

जिला कलेक्टर द्वारा शहर की बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के मद्देनजर आशीष लॉज के पास ऑटो स्टैंड की स्थापना तथा सुविधा एवं आवश्यकता मुताबिक शहर के चारों कोनों पर भी ई रिक्शा स्टैंड का स्थल चिन्हांकन कर प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में यातायात प्रभारी नीलम लक्षकार सहित आरटीओ, सीएमओ, एनएच, पीडब्ल्यूडी एवं एमपीआरडीसी के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राकृतिक झिरिया पुनर्जीवन कार्य जारी

नवभारत न्यूज

पन्ना 26 अप्रैल। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत दक्षिण पन्ना वनमण्डल में प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु वृहद स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं।

विभिन्न वन परिक्षेत्रों में झिरियाओं की सफाई, मरम्मत एवं सुधार कार्यों के माध्यम से जल उपलब्धता बढ़ाई जा रही है, जिससे भीषण गर्मी के दौरान वन्यजीवों एवं पक्षियों को पर्याप्त पेयजल मिल सके। शाहनगर रेंज में बोरी बीट में झिरिया की सफाई का कार्य वनरक्षक प्रेम नारायण वर्मा द्वारा सुरक्षा श्रमिकों के सहयोग से कराया गया। बिसानी बीट में कार्यवाहक वनपाल अनिल प्रताप सिंह एवं वनरक्षक रचना जादौन द्वारा झिरिया पुनर्जीवन एवं सफाई कार्य किया गया। वनरक्षक शिव प्रताप सिंह द्वारा झिरियाओं की मरम्मत, सुधार एवं सफाई कार्य संपन्न कराया गया। बिहरिया बीट में वनरक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा चंदल नाला झिरिया और पन्नी नाला झिरिया की मरम्मत तथा सफाई कार्य करवाया गया।

पवई रेंज में कैमूरिया, झांझर एवं चौपरा बीटों में वनरक्षक विनय सिंह, सचेंद्र मोहन एवं सरोज सिंह द्वारा झिरिया पुनर्जीवन, मरम्मत एवं सुधार कार्य किए गए हैं। साथ ही अरण्य भवन परिसर पवई में विभिन्न जीव-जंतुओं के लिए जलाशय की व्यवस्था सागर सोनी द्वारा की गई है, जिससे छोटे जीवों को भी जल उपलब्ध हो सके। इस प्रकार समन्वित एवं सतत प्रयासों से दक्षिण पन्ना वनमण्डल में प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण करते हुए वन्यजीवों एवं पक्षियों के लिए सुरक्षित एवं निरंतर पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

मोहंद्रा रेंज में अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

पन्ना 26 अप्रैल। आज दक्षिण वन मण्डल पन्ना के मोहंद्रा परिक्षेत्र में अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए लगभग डेढ़ हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण कारियों के कब्जे से मुक्त कराया गया । विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद मौके पर कार्रवाई की गई। भूमि को कब्जामुक्त कराने के साथ ही भविष्य में अतिक्रमण की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वन सीमा पर गहरी खाई (ट्रेंच) खोदने का कार्य भी किया गया है। अतिक्रमणकारी द्वारा कब्जे के संबंध में कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहने के उपरांत, संबंधित के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिक वन अपराध रिपोर्ट दर्ज किया गया है।

जिला जेल पन्ना में लगी विशेष जेल लोक अदालत

नवभारत न्यूज

पन्ना 26 अप्रैल। उच्च न्यायालय जबलपुर एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष शरत चन्द्र सक्सेना की अध्यक्षता में रविवार को जिला जेल पन्ना में विशेष जेल लोक अदालत लगाई गई।

इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जेल लोक अदालत के लिए गठित खंडपीठ की पीठासीन अधिकारी रीतिका पाठक सहित प्राधिकरण के सचिव राजकुमार गौड़ एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन भी उपस्थित रहे। उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने ग्वालियर से सभी केन्द्रीय, जिला एवं उप जेल की विशेष जेल लोक अदालत का ई-उद्घाटन किया। प्रधान जिला न्यायाधीश पन्ना द्वारा विशेष जेल लोक अदालत के संबंध में राजीनामा प्रकरणों की जानकारी लेकर बंदियों से लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण की अपील की गई।

स्लॉट बुकिंग सुविधा 30 से बढ़ाकर 9 मई तक

नवभारत न्यूज

पन्ना 26 अप्रैल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को गेहूं, चना एवं मसूर उपार्जन कार्यों की वीसी के जरिए समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की जवाबदारी कलेक्टर्स की है। मध्यम एवं बड़े कृषकों को गेहूं विक्रय करने के लिए स्लॉट बुकिंग की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है।

स्लॉट बुकिंग की सुविधा 30 अप्रैल से बढ़ाकर अब 9 मई तक की गई है। सभी किसानों का इस अवधि में पंजीयन कराएं। इस अवसर पर कमिश्नरेट सागर में संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी सहित कलेक्टर पन्ना ऊषा परमार एवं अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए की सभी उपार्जन केंद्रों पर कलेक्टर प्रतिदिन निरीक्षण करें एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों का समय पर भुगतान करना भी सुनिश्चित किया जाए। स्वसहायता समूह द्वारा संचालित उपार्जन केंद्रों की

भी लगातार समीक्षा की जाए। बैठक में बताया गया कि सागर संभाग के जिलों में 25 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से मध्यम श्रेणी एवं बड़े किसानों से गेहूं उपार्जन के लिये पूर्व वर्ष अनुसार ही स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पूरे प्रदेश में स्लॉट बुकिंग की तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई 2026 तक की गई है। किसानों की सुविधा के लिए अब प्रत्येक शनिवार को भी स्लॉट बुकिंग एवं उपार्जन का कार्य जारी रहेगा।

उपार्जन केन्द्र पर प्रतिदिन गेहूं विक्रय के लिये स्लॉट बुकिंग की क्षमता 1000 क्विंटल से बढ़ाकर 2250 क्विंटल प्रतिदिन प्रति उपार्जन केन्द्र किया गया है। कृषक द्वारा उपार्जन केन्द्र की प्रतिदिन तौल क्षमता 2250 क्विंटल के मान से स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर तौल कांटों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिससे अधिक संख्या में किसान तथा मात्रा के स्लॉट बुकिंग कराकर गेहूं का उपार्जन किया जा सकेगा। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी न हो एवं उपज विक्रय के लिए इंतजार न करना पड़े इसके लिये किसानों को जिले के किसी भी उपार्जन केन्द्र पर उपज विक्रय करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उपार्जन केन्द्र पर किसानों की सुविधा के लिए पीने का पानी, बैठने के लिए छायादार स्थान, जन सुविधाएं आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों को उपज की तौल समय पर हो सके इसके लिये समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें बारदाने, तौल कांटे, हम्माल तुलावटी, सिलाई मशीन, कम्प्यूटर, नेट कनेक्शन, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण, उपज की साफ-सफाई के लिए पंखा, छन्ना आदि की व्यवस्था की गई है। किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है।